

सुविधा का लेन-देन

इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में यूएनआईड प्रेमेट्स इंटरफेस यानी यूपीआईआई देश में लेन-देन के एक लोकप्रिय और विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित हुआ है। इससे भी बढ़कर भारत की निरंतर डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ भी बना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुश्रवण में दो हजार रुपये से अधिक के लेन-देन पर मचैट डिस्कॉउंट रेट यानी एमडीआर चार्ज का कारोबारियों के ऊपर लागू करने की बात कही गई है। इस घोषणा ने सरल-सुलभ लेन-देन करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के मन में कई सवालों को जन्म दिया है। हालांकि, राहतकारी यह है कि नोटिफिकेशन में दो हजार तक के यूपीआई लेन-देन और सेव डेबिट कार्ड प्रेमेट्स पर कोई शुल्क न लगाने की बात कही गई है। लेकिन इससे देश में अधिक मूल्य वाले यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर चार्ज लगाने का एस्ता खुल गया है। बैंकों, सेवा प्रदाता संस्थाओं व विभिन्न एसएसएनरों के प्रतिनिधित्व जल्द ही दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर चार्ज करेगे। निस्संदेह किसी भी डेबटर सुविधा के लिए उपभोक्ता की भी

आर्थिक जवाबदेही बनती है। उल्लेखनीय है कि साल 2016-17 में महज 0.07 लाख

[illegible]

व्यवहारीक के माध्यम से उपभोक्ताओं पर डाल देंगे। ऐसे में यूपीआई और सेवा नियामक को समझने को स्पष्टता और पारदर्शिता के आधार पर फैसला लेना चाहिए। एचडीआर की रणनीति का निर्धारण कुछ इश्तरेह किया जाना चाहिए, जिससे छोटे व्यवसायों को अधिक बचत बचाव पड़े। लोगों का अपनी लेन-देन प्रमाण ही बना रहे और वे ही दो हजार रुपये की सीमा में बदलाव न किया जाए। आज देश में यूपीआई व्यवस्था त्वरित, सस्ती और सार्वभौमिक भूताना सुविधा के चलते अव्यवस्था की एक बड़ी ताकत बन गयी है। ऐसे में सरकार को भुगतान इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रमेट को नजाराभार के लिए प्रोत्साहन सुलभ रखे। साथ ही उस दांचे को आर्थिक संवर्धन दे जिस पर यह निरभर है।

कुछ

अलग

आत्मा की सत्ता का बोध

आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित एक धर्मगुरु के शिष्यों ने हताश होकर एक कापालिक को शंकराचार्य को हत्या के लिए भेजा। जैसे ही कापालिक ने शंकराचार्य के सामने पहुँचकर तलवार निकाली, उन्होंने कहा— कापालिक, तुम्हारे शरीर और मेरे शरीर में आत्मा कहीं एक ही सत्ता है। तुम किसीका हत्या करना चाहते हो? कापालिक स्वयं धर्म शास्त्रों का पंडित था। शंकराचार्य के शाब्दों ने उसकी आत्मा को झुकझोर डाला। उसने तलवार जमीन पर फेंक दी तथा शंकराचार्य के चरणों में गिरकर बोला, 'महात्मान! वास्तव में मैं एक सत्ता का अस्तित्व भूलकर किसी के बरगलाने पर यह अक्षय्य अपराध करने को उद्यत हो गया था। आपके चरणों में पुझे 'अपने' से परिचित करने के लिए कापालिक शंकराचार्य का शिष्य बन गया। और जीवनपर्यन्त उनके विचारों के प्रचार के लिए समर्पित हो गया।

दृष्टि

कोण

नशा कारोबार की बड़ी मछलियों पर कसै शिकंजा

फुकेते दिल्ली प्रलाइट के पायलट द्वारा कैमबिस (गुंजा) इस्तेमाल करने को शुरूआती जांच रिपोर्टों में भारत में भाग (चरस) के इस्तेमाल और तस्करी पर फिर से ध्यान खींचा है। एक दार्शनिक पायलट द्वारा ऐसा उपयोग दर्शाया है कि चरस को पहुंच सुक्ष्म के लिहाज में महत्वपूर्ण प्रेषित तक हो चुकी है। हाल ही में हुई जल्दी को घटनाओं में इस चुनौती को और उजागर किया है। खबरों के मुताबिक, रॉमिलनाग के ब्रिगमेंस सिटी पुलिस ने 135 कोलेग्राफ़म से ज़्यादा गांजा जप्त किया, जिसे ऑडिशिया से बेजा गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ऑडिशिया की सोनपुर और कंधमाल जिला पुलिस ने भी ट्रकों से लगभग 23,000 कोलेग्राफ़म गांजा जप्त किया है। असम और त्रिपुरा से भी भारी मात्रा में जल्दी की खबरें आ रही हैं। मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर भी

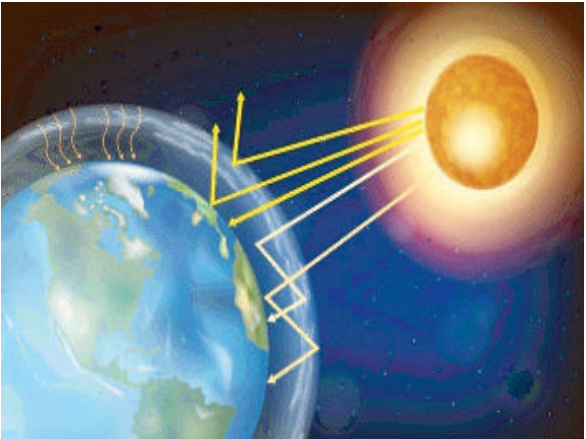
भारी मात्रा में जन्ती की गयी। मुंबई के बोरोली में हाइड्रोपोनिक तरीके से कैनिन के उगाने का पता चला। हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में विविध प्रकार के चरम उत्पादों की भारी जन्ती हो रही है, और तत्पश्चात् इन्हें लाने-ले जाने और वितरण के अलग-अलग ढंग अपना रहे हैं। भारत हर साल हजारों टन हिसाब से गांजा जन्त करती है और हजारों उद्योगगतोंओं पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, आंकड़े बताते हैं कि हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं-एक बड़ी चुनौती, जो वैश्विक व्यापारिक सिस्टम से प्रेरित है, और वाली है। अब इस पर ध्यान देने का सही समय है। 'विश्व मादक द्रव्य रिपोर्ट-2026' (जिसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मादक द्रव्य एवं अपराध विभाग प्रकाशित कर रहा है) कुछ नये पहलू ही प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं। सर्वप्रथम, आज भी दुनिया में

अनियोजित शहरी विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवनशैली, उपभोक्तावाद और एकल- उपयोग वाली वस्तुओं के बढ़ते इस्तेमाल ने शहरों में कचरे की मात्रा और विविधता दोनों को बढ़ा दिया है। अनेक शहरों में कचरे का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण अभी भी मुख्यतः 'कैवट-ट्रांसपोर्ट-डंप' मॉडल पर आधारित है। इसका परिणाम खुले में कचरा फेंकने, जलाने, जल स्रोतों के प्रदूषण, दुर्गंध, वायु प्रदूषण और लैंडफिल के बढ़ते दबाव के रूप में सामने आता है। इसलिए भारत के सामने चुनौती केवल कचरा हटाने की नहीं, बल्कि उसे संसाधन में बदलने की है। भारत के तेज अग्रगण्य की प्रकृति अत्यंत विविध है। घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों से निकलने वाला नगरपालिका तेज अग्रगण्य इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें भोजन और अन्य जैविक पदार्थों के सब्जि कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और पैकेजिंग सामग्री शामिल होती है।

देश

दुनिया से

इंसानी नादानी से उपजी चुनौती और हमारा दायित्व



परत समान नहीं होती। सबमण्डल का ओजो हमरा शक्ति है, जबकि धरातल के पास बनना वाकाल तो प्रोटेक्सीर के अन्तर्गत वायु प्रसृषण का एक महत्वपूर्ण घटक है और मानव स्वास्थ्य तथा वनस्पतियों के लिए हानिकारक है। जलवायु परिवर्तन के दौर में बदती गर्मी, जंगलों की आग और वायुमंडलीय रसायन इन दोनों स्तरों की जटिलताओं को और अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। मॉर्नट्रुल प्रोटोकॉल के कारण लगभग 99 प्रतिशत नियंत्रित ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध किया जा चुका है और वैज्ञानिक आकलन के समय से ओजोन परत के पुनरुद्धार की दिशा में प्रागिकी को पुष्टि करते रहे हैं। हालाँकि, 'नेचर कम्यूनिकेशन' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं के ओजोन-क्षयकारी पदार्थों का फ़ीडबैक के रूप में उपयोग अपेक्षा से कहीं अधिक उत्सर्जन पैदा कर सकता है। यही ये उत्सर्जन वर्तमान स्तरों पर जारी रहे, तो मध्य-अक्षांशों में ओजोन परत की रिकवरी लगभग 7 वर्ष तक पीछे खिसक सकती है। इसके अलावा,

वैज्ञानिकों ने पूर्वी एशिया में हैलॉन-2402 नामक शक्तिशाली ओजोन-क्षयकारी पदार्थ के उत्सर्जन में फिर से बढ़ोतरी के प्रमाण पाए हैं। अध्ययन के अनुसार 2008 से 2023 के बीच पूर्वी एशिया से इस उत्सर्जन का संघर्षी अनुमान लगभग 52 गीगाग्राम सेंटीमीटर-11 डिविजमेंट रहा और 2015 के बाद इस क्षेत्र के उत्सर्जन में वैश्विक प्रवृत्ति को प्रभावित किया है। अप्रैल 2026 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि वैज्ञानिकों ने उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगभग 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर असामान्य रूप से अधिक ओजोन की एक मोटी परत देखी। यह संभावना पूर्वी भारत के लिए सामान्य गहरा से काफी अधिक थी और एक दिन से ज्यादा समय तक बनी रही। भारतीय वैज्ञानिकों ने देशभर के वायुमंडलीय रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मोडलों को एक साथ इस्तेमाल किया। नैनितान्त स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसों के स्पेडशी रॉफ सहित कई केंद्रों से मिले आंकड़ों ने

वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि वायुमंडल में ओजोन का परिवहन किस तरह होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस घटना के पीछे ओजोन-समृद्ध वायु का परिवहन, उसके बाद नीचे की ओर वायुमंडलीय उत्तरी और वायु-दक्षिणमान का संपीड़न प्रमुख कारण थे। यह उदाहरण बताता है कि ओजोन परत कोई स्थिर, समान मोटाई वाली चادر नहीं है। वायुमंडलीय परिसंचरण, हवाएं, तापमान और रासायनिक प्रक्रियाएं लगातार इसकी संरचना और वितरण को प्रभावित करती हैं। भारत और नेपाल का पर्यावरणीय भविष्य अलग-अलग खातों में नहीं बांटा जा सकता। नेपाल में ऊंचाई के कारण पराबैंगनी विकिरण का सवाल विशेष महत्व रखता है। नेपाल के भूरेहवा, पोखरा और लुम्बि में किए गए एक अध्ययन में यूवी इंडेक्स में उल्लेखनीय मौसमी और स्थानिक अंतर दर्ज किए गए। विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले लुम्बि और पोखरा में कुछ अवधि के दौरान यूवी इंडेक्स काफी ऊंचा पाया गया। इसका मतलब यह नहीं कि नेपाल या हिमालय में ओजोन परत खत्म हो रही है, बल्कि संदेश यह है कि ऊंचाई, सूर्य की स्थिति, बादल, वायुमंडलीय संरचना और ओजोन की मात्रा मिलकर सदैव तक पहुंचने वाले यूवी विकिरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए हिमालयी देशों को स्थानीय यूवी निगरानी, मौसम विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां प्रणालियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भारत और नेपाल के लिए यह सहयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तेजी से बदलती परिस्थितियों पर कब्जा कर रहा है। दक्षिण एशिया में गर्मी लगातार बढ़ रही है।

सर्वाधिक इस्तेमाल होनेवाला नशीला पदार्थ गांजे है। साल 2024 में 25.6 करोड़ लोग गांजे का उपयोग करते बताए गए हैं, जो किसी भी अन्य नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करने वालों से ज्यादा है। यह संख्या 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की वैश्विक आबादी का 4.8 प्रतिशत बनती है। वैश्विक दशक में गांजे का सेवन करने वालों की संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी। दूसरा, गांजे की खेती दुनिया के लगभग हर देश में होती है। लेकिन अंतर-क्षेत्रीय क्षेत्रों स्तर पर होती है। लेकिन अंतर-क्षेत्रीय क्षेत्रों बढ़ रही है। उत्तरी अमेरिका में सबसे तस्करी का बढता हुआ स्रोत है। चीन, सिरा, ज्यादा असरकारी गांजा उत्पादों की बढ़ती रजिस्ट्रेशन आ रही है। और, हिंसक 28 तक, उज्बेक, कजाख और अमेरिका के 28

हलाकों में गैर-मैडिकल कामों के लिए भांग की खेती, उत्पादन, बिक्री और उसे अपने पास रखने की इजाजत दे दी गई है। यह चर्चा गंगाराराज, जर्मनी, लक्जमबर्ग और मॉल्डोवा की कुछ ऐसा ही कहिका। हालाँकि, हालिया वर्षों में, नशीले पदार्थों के गैर-मैडिकल इस्तेमाल को नुकसानदेह माना जाने लगा है, जो उत्तरी अमेरिका में लोगों की बदलती सोच में झलकती है। 'तबतः भांग नशीला और इस्तेमाल वैश्विक चुनौती बना हुआ है। भारत के नशा निपटारा ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक: पहली बार, 2025 में 1.38 लाख एण्ड्रू में भांग के पीछे को नष्ट किका गया, जो पिछले पांच सालों में सर्वाधिक है। दूसरी बार, गाँव से जुड़े 71,612 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है।' 628 हजार किको ज़्यादा पाँच ज़बत किका गया, जो 2024 से तो ज़्यादा था लेकिन 2021 और

2022 से कम था। तीसरी बात, 2021-25 के दौरान देशीय के मामलों की क्षेत्रवार संख्या 2,416 से 3,255 के बीच रही। हालाँकि, पिछले पाँच सालों में देशीय की ज़रूती में काफी उतार-चढ़ाव हुआ, इस उतार-चढ़ाव पर नृश निर्यंत्रण ब्यूरो टिप्पणी यकीनी से नहीं कर रहा—सिमांचित कम हुईं। यी तस्करी के ढंग में संभावित बदलाव आया। चौथी बात, हाइड्रोजेनेिक गैरों (ज्यादा असरदार, पोषक तत्वों से भरपूर) की तस्करी से बढ़ी है, खासकर महानगरीयों में। मामलों और जन्न की ईंग मात्रा, दोनों बढ़ी हैं; 2025 से 862 किलोग्राम जन्न जिका गैरों और 687 केस दंड किए गए, जो बीते चार साल (2021-24) की कुल जन्न की और मामलों से भी ज्यादा है। यानी भांग की जन्न और नृच करने की कार्रवाई पहले के मुकाबले अधिक करी हुई है।

, जबकि एनारोबिक डाइजेरेशन से कम अवशेष प्राप्त होते हैं। इससे कम होने के साथ ऊर्जा और कृषि साधन प्राप्त होते हैं। बड़े शहरों में स्लैज ट्रेटिंग तथा बायोगैस संयंत्र परिवहन अत्यंत उपयोगी हैं। इनमें कन्वेयर सिस्टम, फेडर, पंप, क्लस्सिफायर, और आधुनिक संभरण तकनीक के प्रयोग का किया जा सकता है। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था विज्ञान आधारित प्रणालियां तत्त छटाई को और अधिक प्रभावी बनाती हैं। इसलिए स्रोत पर तकनीकी ध्रुवला की बुनियादी कार्य के लिए यांत्रिक पुनःचक्रण और समान प्रकार के प्लास्टिक में गैसों को जलाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। इनसे ईंधन अथवा रासायनिक कच्चा माल प्राप्त करने की संभावना रहती है, लेकिन इनकी ऊर्जा आवश्यकता, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव का जीवन-चक्र मूल्यांकन आवश्यक है। केवल तकनीकी रूप से संभव होना किसी समाधान को स्वतः ठीका नहीं बनाता। कचरे से ऊर्जा उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। निम्नलिखित दृष्टांत और रिप्यूज-डिआक्विड प्यूल तकनीक के माध्यम से ऐसे अवशिष्ट कचरे से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जिसे पुनःचक्रित या जैविक रूप से संसाधित नहीं किया जा सकता। आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियां प्रदूषकों को निश्चित करने में सहायता करती हैं लेकिन भारत के मिश्रित और अधिक नमी वाले क्षेत्रों में नागरपालिका कचरे की ऊष्मीय क्षमता कई बार कम होती है। इसलिए बिना पुनःचक्रण के पूरे मिश्रित कचरे को जलाना उचित रणनीति नहीं माना जा सकता। ऊर्जा उत्पादन को पुनःचक्रण और जैविक प्रसंस्करण का विकल्प नहीं, बल्कि उनके बाद बचने वाले अवशिष्ट कचरे के प्रबंधन का साधन माना जाना चाहिए। अतः वैज्ञानिक लैंडफिल की आवश्यकता कम बनी रहती है, क्योंकि वह प्रकार के कचरे को पुनःचक्रण संभव नहीं है। इंजीनियर्ड लैंडफिल में लाइनर, लिनेट संग्रहण, गैस कैप्चर और भूजल निगरानी जैसे व्यवस्थित प्रणाली को सीमित कार्बन है। भारत में पुराने कचरा स्थलों के लिए बायोमाइनिंग और बायोर्मिटिगेशन भी उपयोगी तकनीकें हैं, जिनके माध्यम से पुराने कचरे से पुनःचक्रण योग्य योज्य सामग्री निकाली जा सकती है और भूमि को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। भारत का अब रैखिक 'उत्पादन-उपयोग-फेंकने' वाली अर्थव्यवस्था से चक्रिय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। 'कचरा उपयोग, पुनः उपयोग, मरम्मत, पुनःचक्रण और संसाधन पुनर्निर्माण' को शहरी नीति का आधार बनाना होगा। उत्पादन उत्तरदायित्व, कचरा उत्पादकों पर उचित शुल्क, कचरा बीनने वालों का औपचारिक तंत्र में समावेशन, बल्क वेस्ट जनरेटर की जवाबदेही और स्थानीय निकायों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदमों होंगे।

आप क

नज़रिया

भारत ने दिखाया आईना

दिखाया

कार्बन उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों की हकीकत बताते हुए इस बात की आलोचना की कि विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा भारत के प्रति व्यक्ति से 6 गुना ज्यादा है किन्तु हैरानी की बात तो यह है कि विकसित प्रायः कार्बन-उत्सर्जन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाल देते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत इस सच्चाई को दुनिया के हर मंच पर बिना किसी भय एवं संकोच के दोहराता है। दरअसल प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित किए जाने का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और वह जी-20 का एक मात्र ऐसा देश है जिसने परिषद में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) में जाड़ाई गई अपनी प्रतिवद्धताओं को तय समय से काफी पहले पूरा कर लिया है। साथ ही यह कि दुनिया यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भारत गैर जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा क्षमता, कार्बन उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति के मामले में विकासशील देशों की हकीकत बताते हुए इस बात की आलोचना की कि विकसित देशों के प्रति व्यक्ति से 6 गुना ज्यादा है किन्तु हैरानी की बात तो यह है कि विकसित प्रायः कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाल देते हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत इस सच्चाई को दुनिया के हर मंच पर बिना किसी भय एवं संकोच के दोहराता है। दरअसल प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किए जाने का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वह जी-20 का एक मात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) में जताई गई अपनी प्रतिबद्धताओं को तय समय से काफी पहले पूरा कर लिया है। सच तो यह कि दुनिया यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भारत गैर जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा क्षमता, कार्बन उत्सर्जन पर रोक जैसे मानकों पर बड़ी ही वुशलता एवं सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यह सही है कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता और जल विद्युत क्षमता तो बड़ी ही है साथ ही देश परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा बिलुल सही है कि विकसित देश सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं और जब क्षतिपूर्ति की बात आती है तो बड़ी सफाई से मुकर जाते हैं। इतिहास विकसित देशों की नीयत से पृथ्वी को गंभीर खतरा हो गया है। विकासशील देशों की आवाज दबाने के लिए विकसित देशों के पास बहुत सारे हथकंडे हैं किन्तु विकसित देशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशों की एकजुटता का अभाव है और यदि किसी एक-दो देशों ने आवाज उठाई भी तो विकसित देश बड़ी बेगमी से उसे अनसुना कर देते हैं। असल में भारत जैसे जिन देशों ने परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयास नहीं हैं, उनके देशों की मुश्किलें पैदा की जाती हैं। भारत को यूरेनियम हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। विकसित देशों को खारखर अमेरिका दोहरी नीति के कारण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी यूरेनियम हासिल कर पाना हमारे देश के लिए मुश्किल हो जाता है। बहरहाल भारत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर तरह के तरीके अपना रहा है किन्तु मुश्किल यह है कि अमेरिका जैसा देश जो पहले भी दादागिरी करता था अब उसका राष्ट्र पति वुड्स यूनिवर्सिटी का तैयार ही नहीं। मतलब करेला नीम पर चढ़ गया है। ऐसे में भारत को किसी से कोई उम्मीद किए बिना ईमानदारी से पर्यावरण संरक्षण पर तेजी से काम करना होगा। भारत की जिम्मेदारी जलवायु परिवर्तन में सुधार की स्थिति को लेकर बहुत बड़ी है किन्तु यदि स्वयं भी अंधे विकसित देशों ने अपनी नीति में व्यापक सुधार नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम अकेले विकासशील देश ही नहीं भुगतेंगे बल्कि विकसित देश भी तृप्त पृथ्वी की अधिक से अधिक संसाधनों के बिना नहीं रहेंगे। इतिहास भारत को चाहिए कि वह ईमानदारी से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रयत्न भी करे और विकसित देशों को चेतावनी दे तब उन्हें आईना भी दिखाता रहे।



बदला जा सकता है, जबकि पदार्थाविक ढाड़जेशन स बायोगैस और जैविक अवशेष प्राप्त होते हैं। इससे डेलैफिल पर दबाव कम होने के साथ ऊर्जा और कृषि के लिए उपयोगी संसाधन प्राप्त होते हैं। बड़े शहरों में विकेंद्रीकृत कम्प्युटरिंग तथा बायोगैस संयंत्र परिवहन लागत और कचरे के अनावश्यक स्थानांतरण को भी कम कर सकता है। सूखे कचरे के लिए मैटेरियल रिक्वरी फैसिलिटी अर्थात् उपयोगी हैं। इनमें कवच्यूर, बेलेट, चुंबकीय पृथक्करण, एयर क्लासिफायर, ऑफ़िकल सॉटिंग और आधुनिक संस्तर तकनीक के माध्यम से कागज, धातु और विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को अलग किया जा सकता है। कुटुमिबुद्धिमत्ता और कंप्यूटर विज्ञान आधारित प्रणालियाँ भविष्य में स्वचालित ढाड़ई को और अधिक प्रभावी बना सकती हैं। हालाँकि, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री में गैले कचरे के मिश्रण से उसकी गुणवत्ता और आर्थिक उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिए स्रोत पर पृथक्करण इस पूरी तकनीकी श्रृंखला की बुनियादी अंश है। प्लास्टिक कचरे के लिए यांत्रिक पुनर्चक्रण उपकरणों का साफ और समान प्रकार के प्लास्टिक में प्रभावी है। कठिन प्लास्टिक के लिए कुछ रासायनिक

का विकल्प नहीं, बल्कि उनके बाद बचने वाले अवधि के प्रबंधन का साधन माना जाना चाहिए। अंततः वैज्ञानिक लैडफिल की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि हर प्रकार के कचरे का पुनःचक्रण संभव नहीं है। इंजीनियर्ड लैडफिल में लाइनरी जैसे संरक्षण, पैस केप्पर और भूलतः निगरानी लाइसेन्सिंग प्रदूषण को सीमित करने हैं। भारत में पुराने कचरा स्थलों के लिए बायोमैडिनेशन और बायोरिमिडिएशन भी उपयोगी तकनीकें हैं। निम्नके माध्यम से पुराने कचरे से पुनःचक्रण योग्य सामग्री निकाली जा सकती है और भूमि को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। भारत को अब रैखिक 'उत्पादन-उपयोग-फेंकने' वाली अर्थव्यवस्था से चक्र्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। 'भस्म' उपयोग, पुनः उपयोग, मरम्मत, पुनःचक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति को शहरी नीति का आधार बनाना होगा। उत्पादक उत्तरदायित्व, कचरा उत्पादकों पर उचित शुल्क, कचरा बीनने वालों का औपचारिक तंत्र में समावेशन, बल्क वेस्ट जेनरेटर की जवाबदेही और स्थानीय निकायों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वाधिक

कार्बन उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों की हकीकत बताते हुए इस बात की आलोचना की कि विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा भारत के प्रति व्यक्ति से 6 गुना ज्यादा है किन्तु हेरानी की बात तो यह है कि विकसित प्रायः कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाल देते हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत इस सच्चाई को दुनिया के हर मंच पर बिना किसी भय एवं संकोच के दोहराता है। दरअसल प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किए जाने का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वह जी-20 का एक मात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) में जताई गई अपनी प्रतिबद्धताओं को तय समय से काफी पहले पूरा कर लिया है। सच तो यह कि दुनिया यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भारत गैर जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा क्षमता, कार्बन उत्सर्जन पर रोक जैसे मानकों पर बड़ी ही वृशलता एवं सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यह सही है कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता और जल विद्युत क्षमता तो बड़ी ही है साथ ही देश परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा बिल्कुल सही है कि विकसित देश सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं और जब क्षतिपूर्ति की बात आती है तो बड़ी सफाई से मुकर जाते हैं।

